देव चटर्जी
मुंबई, 10 जून

रिलायंस होम फाइनैंस लिमिटेड (आरएचएफएल) के ऋण समाधान पर मतदान फिलहाल जारी है लेकिन भारतीय लेनदारों ने रिलायंस कैपिटल की गैर-बैंकिंग फाइनैंस इकाई रिलायंस कमर्शियल फाइनैंस (आरसीएफएल) के लिए सबसे बड़े बोलीदाता के चयन के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

बैंकिंग सूत्रों ने बताया कि बोलीदाता के चयन के लिए मतदान की प्रक्रिया 25 जून को खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही अनिल अंबानी समूह की कंपनी के 9,000 करोड़ रुपये के एक अन्य ऋण का समाधान हो जाएगा। आरसीएफएल के लिए चार बोलीदाताओं में ऑथम इन्फ्रास्ट्रक्चर ऐंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, हॉक कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के साथ कंसोर्टियम में यूवी एआरसी, इनवेंट एआरसी

- बोलीदाता के चयन के लिए मतदान की प्रक्रिया 25 जून को खत्म होगी
- बोलीदाताओं में ऑथम इन्फ्रास्ट्रक्चर ऐंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, हॉक कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के साथ कंसोर्टियम में यूवी एआरसी, इनवेंट एआरसी और अलकेमिस्ट एआरसी शामिल

और अलकेमिस्ट एआरसी शामिल हैं। रिलायंस कैपिटल की इन दोनों सहायक इकाइयों ने ऋण की अदायगी में चूक की थी। इस पर बैंकों ने दोनों कंपनियों के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से 7 जून 2019 को प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क फॉर रिजॉल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड ऐसेट्स डायरेक्शंस 2019 पर जारी परिपत्र के अनुसार ऋण समाधान प्रक्रिया शुरू की थी। रिलायंस होम फाइनैंस और रिलायंस कमर्शियल फाइनैंस के अलावा प्रवर्तक कंपनी रिलायंस कैपिटल ने भी बैंक ऋण की अदायगी में चूक की थी।

इसलिए रिलायंस कैपिटल की परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए अलग से एक प्रक्रिया चल रही है। लेनदार बीमा कंपनियों एवं कई अन्य परिसंपत्तियों की बिक्री कर रहे हैं जिसमें रिलायंस कैपिटल की रियल एस्टेट परिसंपत्तियां भी शामिल हैं।

ऋण की अदायगी में चूक करने पर रिलायंस कम्युनिकेशंस और रिलायंस नेवल ऐंड इंजीनियरिंग लिमिटेड सहित अनिल अंबानी समूह की कई कंपनियों को भारतीय लेनदारों द्वारा दिवालिया अदालतों में घसीटा गया है। हालांकि मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज रिलायंस कम्युनिकेशंस की सहायक इकाई रिलायंस इन्फ्राटेल के लिए सबसे बड़ी बोलीदाता के तौर पर उभरी है जबकि रिलायंस कम्युनिकेशंस के लिए यूवी एआरसी सबसे बड़ी बोलीदाता के तौर पर उभरी है। बाद में आरबीआई ने स्पष्ट किया कि दिवालिया अदालतों में मौजूद कंपनियों के लिए परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियां बोली नहीं लगा सकती हैं।

का अधिग्रहण किया

भारत में व्यापारियों के लिए वित्तीय सेवा कंपनी भारत पे ने गुरुवार को कहा कि उसने एक सौदे के तहत अमेरिकन एक्सप्रेस और आईसीआईसीआई इन्वेस्टमेंट्स स्ट्रैटेजिक फंड से पेबैक इंडिया का अधिग्रहण किया है। सौदे की रकम का खुलासा नहीं किया गया है और यह कंपनी का पहला अधिग्रहण सौदा है।

अधिग्रहण के बाद पेबैक इंडिया भारत पे की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन जाएगी। पेबैक इंडिया की स्थापना 2010 में की गई थी और यह 10 करोड़ से अधिक सदस्यों के साथ सबसे बड़ा मल्टी ब्रांड लॉयल्टी कार्यक्रम है। इसके पास 100 से अधिक ऑफलाइन एवं ऑनलाइन भागीदारों का नेटवर्क है। यह अपने ग्राहकों को अपने साझेदार व्यापारी के आउटलेट पर होने वाले हरेक लेनदेन पर अंक अर्जित करने और उसे भुनाने का अवसर प्रदान करती है। इस अधिग्रहण से भारत पे को अपने व्यापार भागीदारों के लिए मूल्य अनुपात को बेहतर करने में मदद मिलेगी। *बीएस*

वित्त वर्ष 21 में मिले पारिश्रमिक के लिहाज से टीवी नरेंद्रन व कौशिक चटर्जी 10 अग्रणी कर्मचारियों की सूची में शामिल हैं। टीवी नरेंद्रन को 11.08 करोड़ रुपये जबकि चटर्जी को 10.10 करोड़ रुपये सालाना मिल रहे हैं।

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए प्रबंधकीय पारिश्रमिक में हुई बढ़ोतरी की तुलना वित्त वर्ष 2019-20 से नहीं हो सकती क्योंकि कोविड महामारी के कारण वित्त वर्ष 2019-20 में प्रबंधकीय पारिश्रमिक में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। वहीं निदेशकों ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कम पारिश्रमिक लेने का फैसला किया ताकि संसाधन की बचत हो।

समीक्षाधीन अवधि में कंपनी ने कोविड-19 की चुनौतियों के बीच मजबूत प्रदर्शन किया। टाटा स्टील ग्रुप का एकीकृत कर पश्चात लाभ वित्त वर्ष 21 में 8,190 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले के 1,172 करोड़ रुपये के मुकाबले

है। फ्लैट स्टील उत्पादों में मजबूत उपस्थिति वाली कंपनी टाटा स्टील इन्फ्रा मांग के बाद अब लॉन्ग प्रॉडक्ट में अपनी मौजूदगी बढ़ाने पर विचार कर रही है, साथ ही उसका इरादा खनन क्षेत्र पर भी ध्यान देने का है।

फ्लैट स्टील का इस्तेमाल वाहन उद्योग में होता है, वहीं लॉन्ग स्टील का इस्तेमाल निर्माण व बुनियादी ढांचा उद्योग में। इसके अलावा कंपनी ने स्टील रीसाइक्लिंग कारोबार में प्रगति की है और हरियाणा के स्क्रैप प्रोसेसिंग प्लांट से 5 लाख टन का पहला कंसाइनमेंट भेज दिया है।

विदेशी परिचालन के बारे में कंपनी ने कहा है कि यूरोपीय कारोबार (नीदरलैंड व यूके कारोबार को अलग करने समेत) को पुनर्गठित करने की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही वित्त वर्ष 21 में एबिटा में 50 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद टाटा स्टील दक्षिण एशिया के परिचालन को कारोबारी जारी रखने के तौर पर दोबारा वर्गीकृत किया गया है।

एनएचपीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
सीआईएन: L40101HR1975GOI032564
सेक्टर-33, फरीदाबाद-121003 (हरियाणा) भारत

31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही एवं समाप्त वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय परिणामों की विवरणी का सार

(करोड़ रूपए में)

क्र. सं.	विवरण	एकल					समेकित				
		समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष		समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष	
		31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020	31.03.2021	31.12.2020
		अंकेक्षित	अनंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अनंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित
1)	प्रचालनों से कुल आय	1,341.48	2,092.20	1,913.43	8,506.58	8,735.15	1,609.17	2,359.68	2,170.15	9,647.89	10,007.81
2)	कर पूर्व निवल लाभ (असाधारण मदों से पूर्व)	532.74	945.27	448.08	4,098.50	3,608.17	1,024.23	803.93	112.14	4,668.11	3,265.51
3)	कर पूर्व निवल लाभ (असाधारण मदों के पश्चात)	532.74	945.27	448.08	3,913.50	3,608.17	1,024.23	803.93	112.14	4,483.11	3,265.51
4)	अवधि हेतु कर पश्चात निवल लाभ (असाधारण मदों के पश्चात)										
	–कंपनी के स्वामी	404.21	808.12	382.91	3,233.37	3,007.17	427.55	869.21	157.52	3,257.00	2,884.92
	–अनियंत्रित ब्याज	-	-	-	-	-	37.05	92.43	101.31	325.13	459.99
5)	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [लाभ एवं अन्य व्यापक आय सहित (कर पश्चात)]										
	–कंपनी के स्वामी	490.18	790.06	446.37	3,240.57	3,006.55	514.41	850.90	220.12	3,264.37	2,883.33
	–अनियंत्रित ब्याज	-	-	-	-	-	37.90	92.20	100.48	325.29	459.07
6)	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य ₹ 10/– प्रत्येक)	10,045.03	10,045.03	10,045.03	10,045.03	10,045.03	10,045.03	10,045.03	10,045.03	10,045.03	10,045.03
7)	आरक्षित निधि (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि को छोड़कर)				21,602.28	19,938.78				23,045.26	21,335.89
8)	शुद्ध मुल्य				31,647.31	29,983.81				33,090.29	31,380.92
9)	प्रदत्त ऋण पूंजी				24,653.95	24,526.72				24,656.41	24,529.29
10)	ऋण इक्विटी अनुपात				0.78	0.82				0.75	0.78
11)	प्रति शेयर अर्जन (मूल एवं डाइल्यूटिड) (इक्विटी शेयर, अंकित मूल्य ₹10/– प्रत्येक)										
	–विनियामक स्थगन लेखा शेष में गतिशीलता से पूर्व (₹ में)	0.29	0.76	0.34	2.99	2.65	(0.04)	1.18	0.41	3.03	3.46
	–विनियामक स्थगन लेखा शेष में गतिशीलता के पश्चात (₹ में)	0.40	0.80	0.38	3.22	2.99	0.43	0.87	0.16	3.24	2.87
12)	पूंजी विमोचन आरक्षित				2,255.71	2,255.71				2,255.71	2,255.71
13)	डिबेंचर (बॉण्ड्स) विमोचन आरक्षित				1,641.95	1,948.38				1,641.95	1,948.38
14)	ऋण सेवा कवरेज अनुपात (डीएससीआर)				3.62	3.41				4.02	3.25
15)	ब्याज सेवा कवरेज अनुपात (आईएससीआर)				8.03	7.53				8.92	7.17

नोट :

1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 एवं 52 के अंतर्गत स्टॉक एक्स्चेंजेज में दाखिल वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। इन वित्तीय परिणामों का विस्तृत प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजेज की वेबसाइट : www.nseindia.com और www.bseindia.com पर एवं कंपनी की वेबसाइट : www.nhpcindia.com पर उपलब्ध है।
2. आवश्यक्तानुसार पिछली अवधि के आंकड़े पुनर्समूहित/पुन:व्यवस्थित किए गए हैं।

स्थान : फरीदाबाद
दिनांक : 10 जून 2021

एनएचपीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
हस्ता/-
(राजेन्द्र प्रसाद गोयल)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–08645380

जेपी इन्फ्राः पेशकश पर 14 से मतदान

जेपी इन्फ्राटेक की लेनदारों की समिति के सदस्य सुरक्षा समूह और एनबीसीसी इंडिया की पेशकश पर 14 जून से 23 जून तक मतदान करेंगे क्योंकि दोनों बोली दिवालिया संहिता 2016 के मुताबिक पाई गई है। गुरुवार को सीओसी की बैठक हुई और रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल ने सरकारी कंपनी एनबीसीसी से कहा कि वह पहले यमुना एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी से अपनी पेशकश पर मंजूरी ले कि वह लेनदारों को जमीन का एक हिस्सा हस्तांतरिक कर देगी। एनबीबीसी ने कहा है कि वह एनसीएलटी की मंजूरी से पहले यमुना एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी से इस संबंध में मंजूरी हासिल कर लेगी। जेपी इन्फ्राटेक को अगस्त 2017 में कर्ज समाधान के लिए भेजा गया था जब कंपनी 22,000 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाने में नाकाम रही। *बीएस*

बिज़नेस स्टैंडर्ड
दिल्ली संस्करण

बिज़नेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक नंदन सिंह रावत द्वारा द इंडियन एक्सप्रेस (प्रा.) लिमिटेड, ए-8, सेक्टर-7, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर-201301, उ. प्र. से मुद्रित एवं नेहरु हाउस, 4 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित

संपादक: कैलाश नौटियाल

आरएनआई नo WBHIN/2008/24333
पाठक संपादक को lettershindi@bsmail.in पर संदेश भेज सकते हैं।
टेलीफोन - 033-22101314/1022/1600 फैक्स- 033-22101599
सबस्क्रिप्शन और सर्कुलेशन के लिए कृपया संपर्क करें..
सुश्री मानसी सिंह
हेड कस्टमर रिलेशन्स
बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, तीसरी और चौथी मंजिल, बिल्डिंग एच,
पैरागन सेंटर, सेंचुरी मिल्स के सामने, पी बी मार्ग, वर्ली, मुंबई 400 013
ई मेल.. subs_bs@bsmail.in
या 57575 पर एसएमएस करें REACHBS

डिसक्लेमर.. बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट और फीचर लेखों के माध्यम से बाजारों, कॉर्पोरेट जगत और सरकार से जुड़ी घटनाओं की निष्पक्ष तस्वीर पेश करने का प्रयास किया जाता है। बिज़नेस स्टैंडर्ड के नियंत्रण एवं जानकारी से परे परिस्थितियों के कारण वास्तविक घटनाक्रम भिन्न हो सकते हैं। समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्टों के आधार पर पाठकों द्वारा किए जाने वाले निवेश और लिए जाने वाले कारोबारी निर्णयों के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से स्वयं निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है। बिज़नेस स्टैंडर्ड के सभी विज्ञापन सद्भाव में स्वीकार किए जाते हैं। इनके साथ बिज़नेस स्टैंडर्ड न तो जुड़ा हुआ है और न ही उनका समर्थन करता है। विज्ञापनों से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा संबंधित विज्ञापनदाता से ही किया जाना चाहिए। © बिजनेस स्टैंडर्ड प्रा० लि० का सर्वाधिकार सुरक्षित है। बिजनेस स्टैंडर्ड प्रा० लि० से लिखित अनुमति लिए बगैर समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी सामग्री का किसी भी तरह प्रकाशन या प्रसारण निषिद्ध है। किसी भी व्यक्ति या वैधानिक निकाय द्वारा इस तरह का निषिद्ध एवं अनधिकृत कार्य करने पर दीवानी और फौजदारी कार्यवाही शुरु की जाएगी।

कोई हवाई अधिभार नहीं